राजस्थान में मिल रहा है देशभर में सबसे सस्ता रसोई गैस सिलैण्डर-मुख्यमंत्री

जयपुर/सीकर/नागौर, 3 जनवरी (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अंत्योदय के संकल्प को साकार करने हेतु देशभर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है।

- मुख्यमंत्री ने सीकर और नागौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों का अवलोकन किया।
- धोद में पानी की समस्या पर कार्य योजना बना कर शीघ्र काम शुरू होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सीकर की ग्राम पंचायत बोसाना में आयोजित "विकसित भारत संकल्प यात्रा" शिविर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलैण्डर व चूल्हे वितरित किए। इस अवसर पर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, धोद विधायक गोवर्धन वर्मा, खंडेला विधायक सुभाष मील और पूर्व मंत्री सुभाष महरिया सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।

इस यात्रा का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जनहितैषी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री का संकल्प है कि, यात्रा के दौरान कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं रहे, इस हेतु जन भागीदारी की भी आवश्यकता है। उन्होंने आमजन से अपील की कि, वे अपने गांव-मोहल्ले के हर वंचित व्यक्ति को शिविरों के बारे में जानकारी दें। उन्होंने कहा कि, राज्य में आपकी सरकार है, यह आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। उन्होंने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के माध्यम से देशभर में सबसे सस्ता रसोई गैस सिलेंडर प्रदेशवासियों को मिल रहा है और इसके साथ ही, हम संकल्प पत्र के सभी वादों को पूरा करेंगे।

शर्मा बुधवार को सीकर की ग्राम पंचायत बोसाना और नागौर के खिंयाला में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन कर जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रदेशवासियों को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध करवाना है। इसके लिए संकल्प पत्र में किए गए वादे के मुताबिक गैंगस्टरों एवं संगठनात्मक अपराधियों के विरूद्ध एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, बेरोजगार युवाओं के विश्वास को बनाए रखते हुए पेपरलीक एवं नकल माफियाओं पर कार्यवाही करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।

शर्मा ने कहा कि गत वर्षों में महिलाओं पर अत्याचार के मामले बड़े पैमाने पर राजस्थान में सामने आए हैं। हम मातृशक्ति की समुचित सुरक्षा के लिए कृतसंकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

शर्मा ने कहा कि, धोद क्षेत्र में पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए जल्द ही कार्ययोजना बनाकर काम शुरू कराया जाएगा। यहां पर खेल स्टेडियम का निर्माण भी कराएंगे। शर्मा ने कहा कि, राज्य में अब तक 5300 से अधिक स्थानों पर शिविर आयोजित किए जा चुके हैं तथा 65 लाख से अधिक प्रदेशवासियों ने शिविरों में हिस्सा लिया है।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने खिंयाला में स्थानीय लोक देवता दादोजी महाराज (कंवलसी जी महाराज) व दधिमती माताजी के दर्शन किए।

इस अवसर पर सीकर के बोसाना में सांसद सुमेधानंद सरस्वती, धोद विधायक गोवर्धन वर्मा, खंडेला विधायक सुभाष मील, पूर्व मंत्री सुभाष महरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नागौर के खिंयाला में राज्यमंत्री डॉ मंजू बाघमार, डेगाना विधायक अजय सिंह किलक, मेड़ता विधायक लक्ष्मण कलरू, पूर्व विधायक मोहन राम चौधरी एवं श्रीराम भींचर सहित जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

मामा का घर...

भोपाल, 03 जनवरी। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का घर अब मामा का घर होगा।

मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अब चौहान अपने नए शासकीय बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। इस बंगले का नाम उन्होंने 'मामा का घर' रखा है।

नामकरण के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि, पूरा प्रदेश उनका परिवार है। परिवार के रिश्ते कभी पदों से नहीं हुआ करते और ऐसे रिश्ते पदों के साथ नहीं बदलते।

उन्होंने कहा कि, वे जहां रहेंगे, वो प्यार का घर होगा। मामा के घर

- शिवराज सिंह चौहान ने अपने नए शासकीय बंगले का नाम रखा है "मामा का घर"।

से जनसेवा का उनका यज्ञ लगातार चलता रहेगा। भाजपा कार्यकर्ता के नाते पार्टी द्वारा दिए कार्यों को पूरे सेवाभाव से पूरा करेंगे।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "पता बदल गया है, लेकिन मामा का घर तो मामा का घर है। आपसे भैया और मामा की तरह ही जुड़ा रहूँगा। मेरे घर के दरवाजे सदैव आपके लिए खुले रहेंगे।" इसके पहले उन्होंने कल रात सीहोर जिले के शाहगंज में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार..., कई बार राजतिलक होते-होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन वह किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है।

भाजपा में बीस लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी बदलने पर विचार

- राजेन्द्र राठौड़, सतीश पूनिया और भूपेन्द्र यादव को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी।
- भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, जालोर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, टोंक, बाडमेर, जैसलमेर में नये प्रत्याशी की तलाश।

जयपुर, 3 जनवरी (का.सं.)। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 में मिली शानदार जीत के बाद भाजपा में उत्साह है, अब पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मैदान में उतरने की तैयारी पूरी कर ली हैं। ऐसे में 20 सीटों पर नए चेहरों को मौक़ा दिया जा सकता है, क्योंकि 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया था जिसमें से चार को जीत मिली और तीन सांसदों को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में पार्टी उन सांसदों को फिर मौक़ा नहीं देगी। इन 7 सीटों पर उन्ही की जाति के नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी भाजपा कर रही है।

इसके साथ ही भाजपा और भी कई सीटों पर सांसदों को बदलने के मूड में है। ऐसे में इस बार लोकसभा चुनावों में नए चेहरे दिखने को मिल सकते हैं, जिसमें दो दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनियां का नाम शामिल है।

राजस्थान की जोधपुर, पाली, भरतपुर, बाड़मेर-जैसलमेर, कोटा, झालावाड़-बारां, चित्तौड़गढ़, बीकानेर और भीलवाड़ा लोकसभा सीटों पर भी बदलाव हो सकता है। इन चेहरों को फिर से मैदान में उतारे जाने की तैयारी है।

इसके साथ ही भाजपा लोकसभा के साथ ही कुछ बड़े नेताओ में से एक या दो को राज्यसभा भी भेजने की तैयारी कर रही है।

कई सांसद केंद्र में मंत्री भी हैं। उनके काम की समीक्षा भी की जा रही है, जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय होगी।

राजेंद्र राठौड़ को पार्टी राजसमंद या चूरू से लोकसभा के चुनाव में टिकट दे सकती है। राजसमंद से दिया कुमारी सांसद थीं और अब वो राजस्थान में डिप्टी सीएम बन गई हैं। इसलिए उस सीट पर किसी क्षत्रीय को टिकट दिया जाएगा। चूरू सीट भी राजेंद्र राठौड़ के लिए बेहतरीन मानी जा रही है।

लम्बे समय से राजेन्द्र राठौड़ सदन में मुद्दों को उठाने में मुखर रहे हैं, लम्बा संसदीय अनुभव है। भाजपा संगठन के लंबे अनुभवी एवं राजस्थान की भौगोलिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समझ रखने वाले सतीश पूनियां का पिछले काफी समय से शेखावटी में दौरा बढ़ गया है, यह क्षेत्र किसान, जाट और ओबीसी बाहुल्य है। सीकर, झुंझनूं, चुरु और नागौर में, उनके खूब दौरे हुए हैं, साढ़े तीन सालों तक भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए सतीश पूनियां ने पार्टी की मजबूती में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्हें पार्टी ने कई राज्यों में भी चुनाव में जिम्मेदारी दी थी, जहां पर भी पार्टी को जीत मिली थी। ऐसे में सतीश पूनियां को सीकर, झुंझनूं, नागौर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण या अजमेर से पार्टी मैदान में उतार सकती है।

जोधपुर के गजेंद्र सिंह शेखावत और पाली से पी.पी. चौधरी को फिर से चुनाव लड़वाया जा सकता है। अलवर से केन्द्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। दूसरी सीटों की बात करें तो टोंक-सवाईमाधोपुर से राष्ट्रीय मंत्री अल्का गुर्जर या जयपुर मेयर सौम्या गुर्जर, जयपुर शहर से पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व विधायक रामलाल शर्मा, प्रवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक एवं बिजनेसमैन राजू मंगोड़ीवाला, पूर्व मेयर पंकज जोशी, सांसद रामचरण बोहरा, जयपुर ग्रामीण से पूर्व मंत्री राजपाल शेखावत, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी देवेन्द्र झाझड़िया, दौसा से जसकौर मीणा या उनकी बेटी को पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। जयपुर शहर से किसी वैश्य या ओबीसी चहेरे को मौका देने की चर्चा है।

दौसा, भरतपुर, करौली-धौलपुर, बांसवाड़ा, जालौर, श्रीगंगानगर, उदयपुर में नए चेहरों को मौक़ा दिया जा सकता है।

भाजपा को सत्ता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ही गठबंधन चाहती है, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में किसी और पार्टी को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते, वो मायावती की बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में नहीं आने देना चाहते। आप, दिल्ली और पंजाब में दूसरी पार्टियों का खेल खराब करने पर आमादा है।

वक्त की जरूरत है कि पं.बंगाल में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दल एक साथ आ जायें। दिल्ली और पंजाब में आप और कांग्रेस समझौता कर लें। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मायावती, जयन्त चौधरी और कांग्रेस को सीटें दे देनी चाहिये। महाराष्ट्र में तस्वीर साफ है, जहां शरद पवार के नेतृत्व में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे एक साथ हैं। जम्मू-कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ें।

इण्डिया के घटक दलों के मतभेद, भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की उम्मीदों पर पानी फेर सकते हैं। एकमात्र सकारात्मक तस्वीर कांग्रेस से आई जिसने सीटों के बंटवारे का काम 5 सदस्यीय पैनल को सौंप दिया है। ये पांच वरिष्ठ सदस्य हैं, अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश। सीटों के बंटवारे की शुरूआती कवायद के बाद सोनिया गांधी अंतिम फैसला कर सकती हैं और जो भी विरोध व अड़चनें हैं, उन्हें मिटा सकती हैं।

हाई कोर्ट की नसीहत: वकील यूनिफॉर्म में नहीं करें खुद के मामलों में पैरवी

जयपुर, 3 जनवरी (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के डिप्टी सी.एम. पद की शपथ लेने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई 5 जनवरी को तय की है। अदालत ने याचिकाकर्ता वकील को नसीहत देते हुए कहा है कि, वह बतौर याचिकाकर्ता वकील की ड्रेस पहन कर पैरवी नहीं कर सकता।

एक्टिंग चीफ जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता, अधिवक्ता ओ.पी. सोलंकी ने बहस शुरु की। इस दौरान अदालत ने पूछा कि, याचिकाकर्ता कौन हैं, इस पर सोलंकी ने कहा कि, वे स्वयं ही मामले में याचिकाकर्ता हैं। इस पर खंडपीठ ने मामले की सुनवाई से इन्कार करते हुए

- डिप्टी सी.एम. शपथ याचिका की सुनवाई अब 5 को।

कहा कि, बतौर याचिकाकर्ता वकील अपनी ड्रेस में पैरवी नहीं कर सकता। तब याचिकाकर्ता ने ड्रेस उतार कर पैरवी करने के लिए मामले की सुनवाई एक मिनट के लिए टालने की गुहार की, लेकिन अदालत ने समय नहीं देते हुए प्रकरण की सुनवाई पांच जनवरी के लिए तय कर दी। इस मामले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आर.डी. रस्तोगी ने केन्द्र सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि, यह याचिका राजनीति व दुर्भावना से प्रेरित है। दोनों डिप्टी सी.एम. की शपथ में किसी संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना नहीं हुई है। इसलिए याचिका भारी हर्जाने के साथ खारिज की जानी चाहिए।

जनहित याचिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केन्द्र सरकार के सचिव, राज्य के मुख्य सचिव, डिप्टी सी.एम. दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा को पक्षकार बनाया है। जनहित याचिका में कहा गया है कि, देश के संविधान में डिप्टी सी.एम. का कोई पद नहीं है और ना इस पद पर नियुक्ति का कोई प्रावधान है। इसके बावजूद दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा ने खुद को डिप्टी सीएम बताते हुए शपथ ली है। संविधान के तहत केवल मंत्री पद की शपथ ही ली जा सकती है, इसलिए दोनों डिप्टी सी.एम. की शपथ असंवैधानिक है। अत: दोनों डिप्टी सीएम की शपथ व नियुक्तियां रद्द की जाएं।

केजरीवाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पार्टी सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल ने जांच एजेंसी द्वारा उन्हें नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाने के समय को लेकर सवाल उठाया है और कहा है कि यह एक प्रकार से आगामी 2024 के संसदीय चुनावों में उन्हें पार्टी के लिए प्रचार अभियान चलाने से रोकने व पार्टी के प्रचार में बाधा डालने का प्रयास है। दिल्ली सी.एम. को केन्द्रीय जांच एजेंसी ई.डी. ने नोटिस भेजकर 2 नवम्बर को उपस्थित होने के लिए कहा था परन्तु वे उस वक्त उपस्थित नहीं हुए और कहा था कि यह नोटिस "अस्पष्ट" दुर्भावनापूर्ण एवं कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।" ई.डी. की तरफ से केजरीवाल को दूसरा समन 18 दिसम्बर को प्रेषित किया गया था और उसमें संघीय जांच एजेंसी के कार्यालय में 21 दिसम्बर को उपस्थित होने के लिए कहा था, उस दिन भी मुख्यमंत्री केजरीवाल उपस्थित नहीं हुए थे। सी.बी.आई. की ओर से गत वर्ष 17 अगस्त को दर्ज की गई एफ.आई.आर. में संदिग्ध के तौर पर रिपोर्ट में केजरीवाल का नाम नहीं था।

असम में भीषण सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत, सात घायल

गुवाहाटी, 03 जनवरी। असम में गोलाघाट जिले के बलिजान गांव में बुधवार को एक भीषण सड़क हादसे में 12 यात्रियों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए।

पुलिस ने कहा कि, दुर्घटना तब हुई जब पिकनिक के लिए गोलाघाट बाचागांव से तिनसुकिया जा रही एक बस विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से टकरा गई।

गोलाघाट जिला आयुक्त पी. उदय प्रबीन ने मीडिया से कहा कि, बस में 49 यात्री सवार थे। उन्होंने कहा, दुर्घटना की जांच की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, असम के गोलाघाट में सड़क दुर्घटना के कारण लोगों की मौत से दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 'एक्स' पर कहा, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस कठिन घड़ी में प्रशासन घायलों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना है।

"हिमाचल के मैदानी इलाकों में घने कोहरे का "यैलो अलर्ट"

शिमला, 03 जनवरी। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में मौसम साफ होने की वजह से मौसम में गर्माहट है लेकिन मैदानी इलाकों में कोहरे का सितम जारी है। बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी के मैदानी भागों में दोपहर तक सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। इन भागों में दोपहर तक घना कोहरा छाए रहने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर इन मैदानी जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है और इन जिलों में देर रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी क्षेत्रों में आगामी छह जनवरी तक घना कोहरा छाएगा और विज़ीविलिटी कम रहेगी। प्रदेश में आठ जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा।

'भाजपा ने रची ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खेल खेलना चाहती है और सी.बी.आई. और ई.डी. का इस्तेमाल कर रही है।

अधीर ने बताया कि तृणमूल में ममता के गुट और अभिषेक के गुट में पुराना बनाम नया के नाम पर जो भी अंतर्कलह चल रही है। वह अभिषेक से 9 घंटे तक की गई ई.डी. की पूछताछ की देन है। उस दौरान अभिषेक को सारी पटकथा समझाई गई और कहा गया कि अगर वह तृणमूल कांग्रेस का विभाजन कर देते हैं और राज्य में भाजपा की सरकार बनने देते हैं तो उन्हें भ्रष्टाचार के सभी मामलों से बरी कर दिया जाएगा।

अधीर ने दावा किया कि अभिषेक के पास तृणमूल को तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए यह ड्रामा किया जा रहा है। चौधरी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी पार्टी महासचिव हैं फिर भी जूनियर नेता बनर्जी के लिए बड़ी भूमिका मांग रहे हैं तथा युवा पीढ़ी के लिए ज्यादा पद मांग रहे हैं वहीं सुदीप बंदोपाध्याय, शोभनदेब चट्टोपाध्याय जैसे वरिष्ठ नेता पुराने नेताओं की वकालत कर रहे हैं।

ममता बनर्जी और अभिषेक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजनेता कह रहे हैं कि, पार्टी में दो स्पष्ट घटक हैं, एक का नेतृत्व कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी और दूसरे का ममता बनर्जी। संसदीय चुनावों के लिए अभी से दो अलग-अलग सूचियाँ बन गई हैं।

अभिषेक बनर्जी के पास आगामी आम चुनावों के लिए नामों की एक लिस्ट तैयार है और दूसरी लिस्ट ममता बनर्जी ने तैयार कर रखी है। दोनों घटकों का प्रयास है अपने-अपने निष्ठावानों को संसदीय चुनाव मैदान में उतारना। अभिषेक नए चेहरे लाने के लिए शिकायत करते रहे हैं, जबकि, ममता बनर्जी पार्टी के पुराने प्रत्याशियों को रखना चाहती हैं। अभिषेक बनर्जी वरिष्ठ सांसदों की छंटनी के लिए जोर देते रहे हैं। अभिषेक का कहना है कि, उम्र बढ़ने के साथ उत्पादकता कम हो जाती है तथा अक्सर उम्रदराज प्रत्याशी विधायक जैसे मेहनत वाले काम करने में सक्षम नहीं रहते। ममता बनर्जी ने बार-बार हर स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है कि, वरिष्ठ लोगों को हटाना उनके एजैण्डा में नहीं है। इसके विपरीत उन्होंने दावा भी किया था कि, वरिष्ठ पार्टी सदस्य अनुभवी होते हैं तथा उनके कौशल व अनुभवों का उपयोग किया जाना चाहिए।

पार्टी के अन्य भद्रजन अब एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि, पार्टी नेता व सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने यह कहकर कि, ममता की अनुपस्थिति में पार्टी का रखवाला कोई नहीं होगा, पार्टी चीफ ममता से फायदे लेने के प्रयास किए हैं।

दो अन्य पार्टी पदाधिकारी व सांसद खुले आम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। सांसद अर्जुन सिंह की विधायक सोमनाथ श्याम के साथ जोरदार लड़ाई चल रही है। दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं।

महुआ की याचिका पर लोकसभा महासचिव को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

- हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोईत्रा को कोई आंतरिक राहत देने पर विचार करने से इंकार कर दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा महासचिव की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल से कहा कि, तीन सप्ताह में जवाब पेश किया जाए।

नयी दिल्ली, 03 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर बुधवार को लोकसभा महासचिव को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि वह अधिकार क्षेत्र और न्यायिक समीक्षा की शक्ति सहित सभी मुद्दों पर विचार करेगी।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि, कई मुद्दे उठाए गए हैं। वह इस स्तर पर किसी भी मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करना चाहेगी। पीठ ने याचिकाकर्ता को फिलहाल किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने के मुद्दे पर विचार करने से इन्कार कर दिया।

मोइत्रा को कथित तौर पर, अडानी समूह से संबंधित सवाल पूछने के लिए दुबई के एक व्यवसायी के साथ अपने (संसद की सदस्यता से संबंधित) लॉगिन विवरण साझा करने के मामले में संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी करते हुए लोकसभा महासचिव की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करें। पीठ के कहा कि वह इस मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में करेगी।

सुनवाई के दौरान मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी ने अदालत से याचिकाकर्ता को लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने का आग्रह किया।

इस पर पीठ ने कहा, नहीं, नहीं...हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। यह याचिका को अनुमति देने के समान होगा।इसके बाद सिंघवी ने उनकी अंतरिम गुहार पर नोटिस जारी करने की मांग की।इस पर पीठ ने कहा कि वह अगली तारीख पर सभी मुद्दों पर विचार करेगी। दूसरी तरफ मेहता ने पीठ से इस मामले में नोटिस जारी नहीं करने का आग्रह किया। इस पर पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत केवल पहले प्रतिवादी को नोटिस जारी कर रही है।लोकसभा ने आठ दिसंबर को आचार समिति द्वारा मोइत्रा को सांसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की सिफारिश के मद्देनजर उन्हें संसद से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया था।

कूनो में मादा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने कहा कि, यह परिकल्पना साकार होते हुए देखना रोमान्चकारी है। चीता परियोजना में सभी स्तर के अधिकारियों-कर्मचारियों और विशेषज्ञों ने परिश्रम से कार्य किया है। तीन शावकों का जन्म इस परियोजना की सार्थकता को बढ़ जाएगा।

इंडिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एवं तमिलनाडू के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन बैठक में भाग लेने के लिए उपलब्ध नहीं थे।

कांग्रेस की हिन्दी भाषी प्रदेशों-राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनावी हार के बाद आई.एन.डी.आई. गठबंधन की साझेदार पार्टियों के बीच यह सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि पार्टी ने गठबंधन की गतिविधियों को रोक दिया है एवं क्षेत्रीय पार्टियों को चुनाव प्रचार अभियान से बाहर रखा गया था।

अब तक इंडिया गठबंधन के दलों की तीन बैठकें मुम्बई, बेंगलुरू एवं पटना में आयोजित हो चुकी हैं। मुम्बई के सम्मेलन में लगभग 26 पार्टियों के नेताओं ने सहभागिता की थी और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार अभियान चलाने के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया था।

अडानी-हिंडनबर्ग विवाद जांच सेबी से हटाकर एसआईटी को सौंपने की याचिका खारिज

सी.जे.आई. डी.वाई. चन्द्रचूड़ की बैंच ने कहा कि, जांच किसी अन्य एजेंसी को सौंपने का कोई आधार नहीं है

- बैंच ने कहा कि, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जांच किसी और को नहीं सौंपी जा सकती।
- बैंच से सेबी को तीन माह के भीतर जांच पूरी करने के आदेश दिए।

नयी दिल्ली, 03 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने अडानी-हिंडनबर्ग विवाद की जांच भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) से हटाकर विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपने की याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि, जांच किसी अन्य एजेंसी को सौंपने का कोई आधार नहीं है।

पीठ ने पहले से जांच कर रही विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के खिलाफ हितों के टकराव के आरोप को भी निराधार बताया और आरोपों को खारिज करते हुए सेबी को तीन महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया।

पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि, सेबी के नियामक ढ ांचे में दखल देने की इस अदालत की शक्ति सीमित है।

उन्होंने कहा कि, सेबी ने 22 में से 20 मामलों में जांच पूरी कर ली है। सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, हम सेबी को अन्य दो मामलों में तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं।

पीठ ने पिछले साल 24 नवंबर को कहा था कि, वह अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट को वास्तविक स्थिति के रूप में नहीं देख सकता है। इस वजह से उसने सेबी से जांच करने के लिए कहा था।

पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि केवल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर और उसके आदेशों से प्रभावित संस्थाओं को सुने बिना जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और सेबी को नियामक ढ ांचे को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ समिति पर विचार करने के लिए भी कहा है।

शीर्ष अदालत ने वकील विशाल तिवारी, वकील एम एल शर्मा, कांग्रेस नेता जया ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता अनामिका जायसवाल और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर 24 नवंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जनवरी 2023 में प्रकाशित हिंडनबर्ग (अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलिंग फर्म) की रिपोर्ट में गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह की ओर से धोखाधड़ी और स्टॉक हेराफेरी का दावा किया गया था। हालाँकि, समूह ने उस रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण रूप से शरारती कहकर खारिज कर दिया था।

कर्नाटक में एक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अर्चना करने में बाधा उत्पन्न की तो हाथ पर हाथ रखे बैठे नहीं रहेंगे। पूर्व मंत्री ने चेतावनी देते हुए जवाब दिया कि "यदि किसी भी व्यक्ति ने हमें हमारे भगवान की पूजा करने में व्यवधान पैदा करने की कोशिश की तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं सबक सिखाएंगे। राम भक्त चुपचाप नहीं बैठेंगे। यदि वो मैदान में एक बार उतर गए तो कांग्रेस किसी भी परिस्थिति में मुकाबला नहीं कर पाएगी। यदि 22 जनवरी 2024 को कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी जवाबदेही सीधे तौर पर हरिप्रसाद की होगी।"

दुर्भाग्यवश हरिप्रसाद ने राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को एक धार्मिक कार्यक्रम के बजाए एक राजनैतिक समारोह बताया है, अनेक कांग्रेस नेताओं ने भी कार्यक्रम को लेकर यही बात कही है। हरिप्रसाद ने कहा कि "यदि यह एक धार्मिक समारोह होता तो हम सब इस कार्यक्रम में उपस्थिति होते। उद्घाटन का यह कार्यक्रम किसी धर्म गुरू ने नहीं बनाया है बल्कि यह विश्व गुरू के द्वारा निर्मित कार्यक्रम है।" हरिप्रसाद का यह इशारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ था, जिनका उनके अनुयायियों ने विश्व गुरू के रूप वर्णन किया है।

हरिप्रसाद ने चुटकी ली और कहा कि "हम विश्व गुरू और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के धर्म के बारे में नहीं जानते।"

ज्ञातव्य है कि गुजरात में वर्ष 2002 में गोधरा यात्री ट्रेन अग्निकांड हुआ था उस समय गोधरा रेलवे स्टेशन के निकट साबरमती एक्सप्रैस ट्रेन में आग लगी थी और उस भीषण घटना में अयोध्या से वापस लौट रहे कार सेवक 59 हिन्दू तीर्थ यात्री थे जो जल कर मर गए थे। इस ट्रेन अग्निकांड के बाद गुजरात प्रदेश में हुए दंगों में लगभग 2000 लोगों की मृत्यु हुई थी।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600